बेरोज़गार युवाओं को सशक्त बनाने के लिये समझौता ज्ञापन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, **अपैरल ट्रेनिंग एंड डिज़ाइन सेंटर (ATDC),** गुरुग्राम और **साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (SECL)**, बिलासपुर ने आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के वंचित युवाओं के लिये व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने के लिये एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये।

मुख्य बिंदु

- **समझौते के बारे में:**
  - इस कार्यक्रम का उद्देश्य कौशल आधारित प्रशिक्षण प्रदान करके आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के वंचित युवाओं का उत्थान करना है।
- **CSR पहल:**
  - यह पहल साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (SECL) के कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) प्रयासों का हिस्सा है।
    - इसके तहत 400 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित करने के लिये कुल 3.12 करोड़ रुपए आवंटित किये गये हैं।
- **प्रशिक्षण कार्यक्रम संरचना:**
  - गैर-आवासीय प्रशिक्षण:
    - ATDC **स्वरोज़गार दर्जी कार्यक्रम** के तहत 300 उम्मीदवारों के लिये प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करेगा।
    - SECL **बिश्रामपुर, सोहागपुर और कोरबा क्षेत्र में प्रशिक्षण केंद्र स्थापित** किये जाएंगे।
- **आवासीय प्रशिक्षण:**
  - 100 अभ्यर्थियों को मध्य प्रदेश के **छिंदवाड़ा स्थित ATDC प्रशिक्षण केंद्र में पूर्णतः आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम से गुजरना होगा।**
  - इस कार्यक्रम में निःशुल्क भोजन और आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
  - अभ्यर्थियों का चयन SECL प्रतिष्ठानों के 25 किलोमीटर के दायरे से किया जाएगा।
- **उद्देश्य:**
  - कोयला मंत्रालय के मार्गदर्शन में इस पहल के उद्देश्य हैं:
    - कोयला क्षेत्र में वंचित युवाओं को सशक्त बनाना।
    - स्वरोज़गार और नौकरी के अवसर सृजित करना।
    - विकसित भारत के विज़न में योगदान देना।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR)

- सामान्य तौर पर CSR को पर्यावरण पर कंपनी के प्रभाव और सामाजिक कल्याण पर प्रभाव का आकलन करने और ज़िम्मेदारी लेने के लिये एक **कॉर्पोरेट पहल** के रूप में संदर्भित किया जा सकता है।
- यह एक स्व-विनियमन व्यवसाय मॉडल है जो किसी कंपनी को सामाजिक रूप से जवाबदेह बनने में मदद करता है। **कॉर्पोरेट सामाजिक ज़िम्मेदारी का पालन करके, कंपनियाँ आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय कारकों पर पड़ने वाले प्रभाव के प्रति सचेत रहती हैं।**
- भारत पहला देश है जिसने कंपनी अधिनियम, 2013 **के खंड 135** के अंतर्गत संभावित CSR गतिविधियों की पहचान के लिये रूपरेखा के साथ CSR को अनिवार्य बनाया है।
  - भारत के विपरीत, **अधिकांश देशों में स्वैच्छिक CSR व्यवस्थाएँ हैं। नॉर्वे और स्वीडन,** जो अनिवार्य CSR प्रावधानों की ओर बढ़ चुके हैं, ने स्वैच्छिक मॉडल के साथ शुरुआत की थी।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/mou-for-empowering-unemployed-youth